भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1555

04 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

फोर्टिफाइड चावल

1555. श्री जी. कुमार नायक:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चरण I और चरण II के कार्यान्वयन के बाद फोर्टिफाइड चावल वितरण के पोषण संबंधी प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए चावल फोर्टिफिकेशन को प्राथमिकता देने के पीछे क्या तर्क हैं और क्या योजना शुरू करने से पहले वैकल्पिक पौष्टिक खाद्य विकल्पों पर विचार किया गया था;

(ग) क्या चावल फोर्टिफिकेशन योजना को लागू करने से पहले राज्यों से परामर्श लिया गया था और यदि हां, तो राज्यों से लिए गए परामर्श और प्राप्त इनपुट का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या फोर्टिफाइड चावल की तुलना अन्य पोषण कारकों से करने के लिए कोई पायलट अध्ययन या मूल्यांकन किया गया था और यदि हां, तो इन मूल्यांकनों के परिणाम क्या थे; और

(ड.) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत अन्य संभावित आहार की तुलना में फोर्टिफाइड चावल का चयन करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): नीति आयोग ने चावल फोर्टिफिकेशन पहल के मूल्यांकन प्रभाव को मॉनीटर करने के लिए एक कोर समिति गठित की है। नीति आयोग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पोषण संस्थान (आईसीएमआर-एनआईएन) ने भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति किए गए आयरन फोर्टिफाइड चावल के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए देश के छः विभिन्न राज्यों में छः जिलों में अध्ययन किया है। इस अध्ययन में सभी आयु समूह शामिल हैं, एक टाइम-सीरीज़, रिपीट क्रॉस-सेक्शनल डिज़ाइन को लागू किया गया है और लगभग 10,000 व्यक्तियों को कवर किया गया है।

...2/-

इसके साथ ही, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चावल फोर्टिफिकेशन पर गुणकारिता और प्रभावशीलता का अध्ययन किया। इस अध्ययन में, चावल फोर्टिफिकेशन की शुरूआत करने के बाद बच्चों (6-59 माह) में 65.7% (बेसलाइन: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, जनवरी 2021) से 58.2% (एंडलाइन: जुलाई-अगस्त 2023) की दर के साथ एनीमिया में 7.5% की महत्वपूर्ण कमी दर्शायी गई है।

(ख): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के तहत भारत सरकार द्वारा तीन प्रकार के खाद्यान्न आबंटित किए जाते हैं; नामत: चावल, गेहूं और मोटा अनाज जिनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चावल सर्वाधिक मात्रा में आबंटित किया जाता है।

भारत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए चावल एक आदर्श माध्यम है क्योंकि 65% आबादी एक प्रमुख आहर के रूप में इसका उपभोग करती है। चावल आपूर्ति श्रृंखला पहले से ही सुव्यवस्थित है और चावल मिलों में मिल्ड किए गए धान को प्राकृतिक आपूर्ति श्रृंखला का ऐसा भाग माना जाता है जहां फोर्टिफाइड चावल तैयार करने के लिए फोर्टिफिकेंट्स को ब्लेंड किया जाता है।

(ग): नीति आयोग, महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ बैठक आयोजित की गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि खाद्य फोर्टिफिकेशन में चावल को रोल आउट करते हुए मार्च, 2019 से प्रत्येक राज्य में एक जिले को कवर किया जाएगा। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-2020 की शुरुआत से 3 वर्षों की अवधि के लिए "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल का फोर्टिफिकेशन और उसका वितरण" पर केन्द्रीय प्रायोजित पायलट स्कीम को अनुमोदित कर दिया गया। ग्यारह राज्यों ने इस पायलट योजना को लागू किया और अपने चिह्नित जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित किया।

चावल फोर्टिफिकेशन पहल (2021-24) का संवर्धन करने और दिसंबर, 2028 तक इसे जारी रखने का निर्णय लेने से पहले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श किया गया है। स्वास्थ्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस पहल को समर्थन दिया है।

....3/-

(घ): खाद्य फोर्टिफिकेशन वैश्विक रूप से मान्यताप्राप्त हस्तक्षेप है जिससे सूक्ष्म पोषक कमियों के बोझ को कम किया जा सके। यह एनीमिया मुक्त भारत के तहत किए गए उपायों में से एक है और चावल फोर्टिफिकेशन पहल एक अनुपूरक रणनीति है जिसका उद्देश्य एनीमिया के प्रसार को कम करना है।

कोक्रेन रिव्यू में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, जिसमें 1,634 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए सात यादृच्छिक नियंत्रित डाटा का विश्लेषण किया था, फोर्टिफाइड चावल का उपभोग करने वाले व्यक्तियों के बीच एनीमिया का जोखिम 28% तक कम हुआ था। वर्ष 2023 में आईसीएमआर-एनआईएन द्वारा प्रकाशित "भारत में आयरन-फोर्टिफाइड चावल की प्रभावोत्पादकता और सुरक्षा" शीर्षक वाला श्वेत पत्र यह दर्शाता है कि आयरन की कमी को नियंत्रित करने के लिए चावल फोर्टिफिकेशन एक मध्यावधि रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है।

(ङ.): जैसा भाग (ख) के उत्तर में दिया गया है।

*****